गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक:331
दि. 04.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आईएनएस तारागिरी नेवी में शामिल हुआ:यह ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस

राजनाथ बोले- सेना की ताकत बढ़ेगी

नई दिल्ली,एजेंसी। INS तारागिरी शुक्रवार को विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी में शामिल हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो। हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। INS तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नेवी की ताकत और बढ़ेगी।

तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17-ए के तहत तैयार किया है। वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एमएफस्टार(रडार), मीडियम रेंज सर्फेस टु एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है।

इसके अलावा यह 76 मिमी गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी क्लोज-इन वेपन सिस्टम के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉरपीडो से भी लैस है। वहीं भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन 'अरिदमन' को भी नेवी में शामिल किया गया।

यह नीलगिरि-क्लास का चौथा युद्धपोत है : भारत की नीलगिरी क्लास (Project 17A) में कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। तारागिरी इस क्लास का चौथा युद्धपोत है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्रोजेक्ट 17-ए युद्धपोत को आगे आने वाली समुद्री चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

'तारागिरी' उसी नाम के पुराने युद्धपोत का एडवांस्ड वर्जन है, जिसने 1980 से 2013 तक नौसेना में 33 सालों तक सेवा दी थी। नई 'तारागिरी' हाईटेक स्टेल्थ तकनीक, बेहतर मारक क्षमता, अत्याधुनिक ऑटोमेशन और मजबूत सर्वाइवेबिलिटी से लैस है।

इस युद्धपोत को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट 17-ए के युद्धपोत में पिछली पी-17 (शिवालिक) क्लास की तुलना में अधिक आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं।

अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली लड़की हिंदू निकली

खिलौना पिस्टल दिखाकर 3.6 लाख का हार लूटा, बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से भागी थी

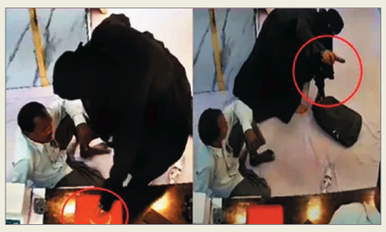

अयोध्या,एजेंसी। अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली लड़की हिंदू निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का नाम पायल (25) और लड़के का नाम राहुल (27) है।

वारदात के वक्त राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख का सोने का हार और चेन लूट ली। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची। उसके साथ बाइक से फरार हो गई। गुरुवार को 12.30 बजे हुई वारदात ज्वैलरी की दुकान में लगे 6 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। घटना रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी बाजार की है। राम मंदिर से घटनास्थल की दूरी करीब 45 किमी है।शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल ने बाजार से नकली पिस्टल और बुर्का खरीदा। पहचान छिपाने के लिए पायल ने बुर्का पहनकर वारदात की। जिस बाइक से दोनों फरार हुए थे, कैमरे में उसका नंबर कैद हो गया था। इसे ट्रेस कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में एवलांच की आशंका

म.प्र.-राजस्थान और हरियाणा में बारिश, 9 राज्यों में अलर्ट; दिल्ली में धूलभरी आंधी चली

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/शिमला,एजेंसी। देश के कई राज्यों में अगले तीन दिन मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एवलांच की आशंका जताई गई है। हिमाचल के अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल इलाके में एवलांच के खतरे को देखते हुए पर्यटकों की एंट्री पर रोका लगा दी है। वहीं जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में लोगों को पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

इधर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में गुरुवार को बारिश हुई। मऊगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं राजस्थान के सभी जिलों में आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। जैसलमेर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई।

हरियाणा के हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में गुरुवार को आंधी चली। दो दिन पहले हुई बारिश में करीब 100 गांवों में गेहूं, सरसों और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में भी शुक्रवार सुबह धूलभरी आंधी चली। इससे कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम हो गई।

ममता बोलीं- वोटर लिस्ट में घुसपैठिए तो मोदी कैसे जीते, पहले वे इस्तीफा दें

तमिलनाडु में बीजेपी के 27 उम्मीदवार घोषित, केंद्रीय मंत्री मुरुगन को टिकट

नई दिल्ली/ कोलकाता/ चेन्नई, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। ऐसे में उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। ममता ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि अधिकारियों के तबादले इस तरह किए गए, जिससे बाहरी लोगों का पश्चिम बंगाल में आना आसान हो सके। मालदा में दो दिन पहले न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना पर ममता बनर्जी ने AIMIM और ISF को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी इस मामले में उकसाने का आरोप लगाया।

इधर, तमिलनाडु में भाजपा ने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को अविनाशी (SC) सीट से टिकट दिया है।

कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया, मोदी सरकार ने बजट बढ़ाया :असम के गोलपाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने आती है, लेकिन उसने आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए कभी काम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि 75 साल तक कांग्रेस ने किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। कि मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण के बजट में भी बड़ा इजाफा किया। उन्होंने कहा कि आजादी से 2013 तक आदिवासी विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर 1.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया।

अमित शाह बोले- सभी घुसपैठियों की पहचान कर ली है, एक-एक को हटाएंगे

असम के गोलपाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार दो बार बन चुकी है और सभी घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि समय कम था, लेकिन अगर उन्हें पांच साल और दिए गए तो चिन्हित घुसपैठियों को एक-एक कर हटाया जाएगा।

अब हाईकोर्ट में आमने-सामने होंगे राहुल गांधी और कार्तिकेय

- भोपाल MP-MLA कोर्ट के समन को राहुल ने दी चुनौती, अगले हफ्ते सुनवाई

जबलपुर,एजेंसी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और शिवराज परिवार आमने-सामने होंगे। मामला मानहानि केस से जुड़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच एक सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगी।

29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में किया था पनामा पेपर लीक का जिक्र : यह विवाद 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। हालांकि, बाद में राहुल ने इसे कंप्यूजन बताया था, लेकिन कार्तिकेय ने इसे छवि खराब करने की साजिश बताते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया।

अमेरिका ने जंग के बीच 3 आर्मी अफसरों को हटाया

राष्ट्रपति ट्रम्प बोले: ईरान से डील नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति दोषी, समझौता हुआ तो क्रेडिट मेरा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जंग के बीच आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा दो और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी पद से हटाने का फैसला किया है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हटाए गए अफसरों में आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के चीफ जनरल डेविड होडने और आर्मी के चैपलिन कॉर्प्स के चीफ जनरल विलियम ग्रीन जूनियर शामिल हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान से समझौते को लेकर कहा, 'अगर यह डील नहीं हुई, तो मैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को दोषी ठहराऊंगा। अगर यह हो जाती है, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट लूंगा।' ट्रम्प ने यह बात व्हाइट हाउस में आयोजित इस्टर लंच के दौरान मजाक करते हुए कहा।

होर्मुज पर ह्न में वोटिंग टली, अब शनिवार को होगा फैसला :

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (ह्नस्ट) में बहरीन के प्रस्ताव पर आज होने वाली वोटिंग कल के लिए टाल दी गई है। इस प्रस्ताव में देशों को होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित के जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात कही गई है। बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इसका मकसद दुनिया के बाजार को सुरक्षित रखना और सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक में रुकावट को रोकना है।

पाकिस्तान में गाय-भैंस पालने पर गोबर टैक्स लगाने की तैयारी

हर पशु पर रोजाना 30 रुपए वसूलेगी सरकार, विपक्ष बोला- यह रेवेन्यू जुटाने का तरीका

लाहौर,एजेंसी। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाय और भैंस पालने पर अब 'गोबर टैक्स' लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर रोजाना 30 पाकिस्तानी रुपए फीस देने का नियम बना सकती है।

सरकार इस कदम को ग्रीन एनर्जी के रूप में पेश कर रही है। यह योजना 'सुथरा पंजाब' बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताई जा रही है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। इसका मकसद कचरे को साफ करना और उससे बायोगैस बनाकर ऊर्जा तैयार करना है।

चारधाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया, रजिस्ट्रेशन में गिरावट

बुकिंग लेने से कतरा रहे ट्रैवल ऑपरेटर्स; पर्यटन व्यवसायियों की बढ़ीं मुश्किलें

देहरादून,एजेंसी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा पर इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात का गहरा साया मंडरा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही बुकिंग में आई गिरावट ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल यात्रा के शुरुआती 26 दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया था। इस साल स्थिति उलट है; अब तक केवल 11,07,841 श्रद्धालुओं ने ही पंजीकरण कराया है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में आई यह गिरावट पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है।

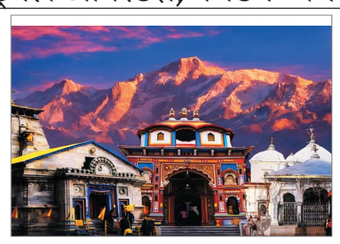

फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक :सरकार ने 15 दिन में फैसला बदला

कई एयरलाइंस ने आपत्ति जताई थी

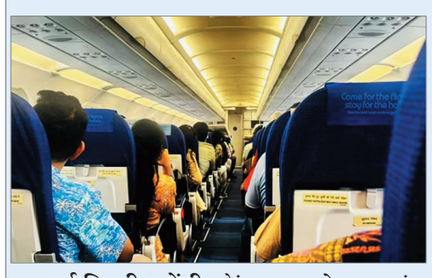

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था।मंत्रालय के अनुसार, इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से आपत्तियां भेजी गई। इनमें ऑपरेशनल असर, किराए पर प्रभाव और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था से तालमेल जैसे मुद्दे उठाए गए। मंत्रालय ने कहा कि व्यापक जांच पूरी होने तक 60% सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।

मौजूदा नियम 20% सीटों पर ही लागू होता है : मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है।

1971 के नायक रहे राजस्थान के सपूत को बांग्लादेशी सम्मान

22 साल की उम्र में अंतिम सांस तक पाकिस्तानी ठिकानों पर करते रहे थे बमबारी

पिलानी (झुंझुनूं),एजेंसी। 1971 के भारत-पाक युद्ध में मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पिलानी (झुंझुनूं) के शहीद धर्मपाल डूडी के अदम्य साहस को आधी सदी बाद एक नई पहचान मिली है। बांग्लादेश सरकार ने शहीद के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उनके परिवार को 'विशेष प्रशस्ति पत्र' और 'राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न' भेंट किया।गुरुवार को जब सेना के अधिकारी यह सम्मान लेकर शहीद के पैतृक गांव धींधवा पहुंचे, तो पूरा माहौल 'शहीद धर्मपाल अमर रहे' के नारों से गूंज उठा।

54 साल का इंतजार, 2018 में जारी हुआ था पत्र, अब पहुंचा घर :बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के हस्ताक्षरों वाला यह सम्मान पत्र 27 नवंबर 2018 को जारी किया गया था।

प्रशासनिक कारणों से इसे पहुंचने में देरी हुई, लेकिन गुरुवार दोपहर 2:30 बजे जब 65 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट विक्रांत, हवलदार रामबीर और अग्निवीर जीतू सिंह गांव पहुंचे, तो शहीद की यादें फिर ताजा हो गईं। जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें सलामी दी।

अराजकता से घिरा बंगाल

संपादकीय

अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे कि बंगाल प्रशासन अराजकता से दृढ़ता से निपटना सीखे-केवल चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी। यदि इस पर ध्यान नही दिया गया तो बंगाल में अराजकता और बढ़ेगी ही।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के काम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तैनात न्यायिक अधिकारियों को जिस तरह घंटों बंधक बनाए रखा गया, वह इस राज्य में अराजकता हावी हो जाने का एक और प्रमाण ही है। इसी कारण इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मालदा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

इस घटना की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिन अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उनमें महिलाएं भी थीं और उन्हें तब मुक्ति मिल सकी, जब खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सख्त आदेश दिए। चूंकि राज्य के शीर्ष अफसर बंधक बनाए गए न्यायिक अधिकारियों को छुड़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस घटना की जांच सीबीआइ या एनआइए से कराने के निर्देश दिए। इसका अर्थ है कि उसे राज्य के शासन-प्रशासन पर तनिक भी भरोसा नहीं।

यह बंगाल सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए, लेकिन यह तय है कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यदि ममता सत्ता में लौटीं तो बंगाल में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ऐसी अराजक घटनाएं फिर से आम हो सकती हैं। हिंसक घटनाओं के सामने पुलिस प्रशासन के मूकदर्शक बने रहने के मामलों में बंगाल सरकार को हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से न जाने कितनी बार फटकार लग चुकी है, पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला है।

मालदा की शर्मनाक घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। यदि सच में ऐसा है तो फिर उनकी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह क्यों किया कि वह अपनी इस टिप्पणी को हटा ले कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? वास्तव में ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना निरा झूठ है कि चुनाव वाले राज्य में सरकार शक्तिहीन हो जाती है। सच यह है कि ममता शासन में बंगाल प्रशासन का बुरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है और कई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जिन अराजक तत्वों ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया, उन्हें वोटर लिस्ट से नाम कट जाने वाले क्षुब्ध वोटरों की संज्ञा देना सुप्रीम कोर्ट को धोखा देना ही है। मालदा में मनमानी करने वाले अराजक तत्व ही थे, इसका पता इससे चलता है कि गत दिवस उन्होंने फिर से उत्पात मचाया और पुलिस पर हमला किया।

निरंतर सीखना, क्षमता-आधारित शासन और कर्मयोगी दृष्टि

विनोद कुमार सिंह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के निर्माण में सिविल सेवा का नया प्रतिमान स्थापित करेगा बदलते वैश्विक परिदृश्य, तीव्र तकनीकी विकास और नागरिक अपेक्षाओं के विस्तार के इस दौर में शासन की प्रकृति भी तेजी से परिवर्तित हो रही है।ऐसे समय में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रारंभ 'कर्मयोगी साधना सप्ताह' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के व्यापक रूपांतरण का सशक्त संकेत है। यह पहल 'नागरिक देवो भव' की भावना को केंद्र में रखते हुए सेवा, संवेदना और दक्षता के नए मानक स्थापित करती है–जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न से जुड़ी हुई है।नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यह सप्ताह मिशन कर्मयोगी के पाँच वर्ष पूर्ण होने का भी प्रतीक है।यह वह पड़ाव है जहाँ उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए भविष्य की दिशा तय की जा रही है।इस पहल का उद्देश्य केवल कौशल विकास नहीं, बल्कि एक ऐसी सिविल सेवा का निर्माण करना है,जो सक्षम, उत्तरदायी,पारदर्शी और पूर्णतः नागरिक-केंद्रित हो।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'विकसित भारत 2047' केवल आर्थिक प्रगति का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टि है।यह एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो आत्मनिर्भर,समावेशी, तकनीकी रूप से अग्रणी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्था भी उसी अनुरूप विकसित हो - जहाँ निर्णय त्वरित हों, सेवाएँ सुलभ हों और नागरिकों का विश्वास सर्वोपरि हो।इसी संदर्भ में प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भविष्य की सिविल सेवा के लिए 'निरंतर सीखना' अनिवार्य है।अब प्रशिक्षण एक बार का औपचारिक चरण नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन चुका है-जहाँ अधिकारी 'कहीं भी,कभी भी' सीख सकते हैं। द्वत्नह्ज्ञ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन को गति दे रहे हैं,जो लाखों कर्मियों को ज्ञान और कौशल से जोड़ रहे हैं।डॉ. मिश्रा ने शासन के नियम- आधारित ढाँचे से भूमिका-आधारित मॉडल की ओर संक्रमण को भी रेखांकित किया।यह बदलाव विकसित भारत की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रशासन को अधिक लचीला,परिणामोन्मुख और नवाचार-प्रधान बनाता है। अब अधिकारी केवल नियमों के पालनकर्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक और समाधान के निर्माता बन रहे हैं।क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान ने मिशन कर्मयोगी को ज्ञान,कौशल और मूल्यों के समन्वय का मॉडल बताया। वास्तव में 'कर्मयोगी' का अर्थ ही है-कर्तव्य को साधना के रूप में अपनाना। यही वह भावना है जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को वास्तविक धरातल पर उतार सकती है।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह द्वारा प्रस्तुत आँकड़े इस मिशन की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं - द्वत्नह्ज्ञ प्लेटफॉर्म पर करोड़ों पंजीकरण और पाठ्यक्रम पूर्ण होना इस बात का संकेत है कि सीखने की यह संस्कृति अब जमीनी स्तर तक पहुँच रही है।यहाँ यह समझना आवश्यक है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शासन की 'अंतिम मील डिलीवरी' मजबूत हो। योजनाएँ तभी सफल मानी जाएँगी जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।इसी उद्देश्य से 'कर्मयोगी क्षमता कनेक्ट' और 'कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम' जैसी पहलें जमीनी स्तर के कर्मचारियों को सशक्त बना रही हैं।सुब्रमण्यम रामदोराई ने जिस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों में दक्षता पर बल दिया, वह इस बात का संकेत है कि भविष्य का प्रशासन डिजिटल और डेटा-आधारित होगा। इसके साथ ही मानवीय संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है।विकसित भारत केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं,बल्कि मानवीय मूल्यों से समृद्ध भी होना चाहिए।

कर्मयोगी साधना सप्ताह का 'प्रौद्योगिकी, परंपरा और ठोस परिणाम' पर आधारित ढाँचा इस संतुलन को स्पष्ट करता है।यह आधुनिकता और परंपरा के समन्वय के माध्यम से स्थायी और प्रभावी शासन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। आज जब विश्व अनेक चुनौतियों -जलवायु परिवर्तन,वैश्विक अस्थिरता और तीव्र शहरीकरण का सामना कर रहा है,तब भारत का यह मॉडल एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

नागरिक देवो भव:भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की ओर एक निर्णायक यात्रा

आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब संसद या मंत्रालय नहीं,उसका स्थानीय सरकारी तहसील कार्यालय, नगर निगम,पुलिस स्टेशन, सरकारी अस्पताल ही सरकार का चेहरा होता है–समग्र विश्लेषण भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, सामाजिक विश्वास का हनन–नागरिक सर्वोपरि और उसकी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है अपने की ज़रूरत भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस क़रने,डेडलाइन बनाने के साथ –साथ शासकीय रुतबे को त्यागने, सेवा को अपनाने नागरिक देवो भव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का संकल्प लेना ज़रूरी वैश्विक स्तरपर भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र सदियों से अतिथि देवो भव रहा है, जिसने न केवल सामाजिक मूल्यों को आकार दिया,बल्कि भारत की वैश्विक पहचान भी स्थापित की।किंतु आज के परिवर्तित समय में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस मंत्र को एक व्यापक और अधिक समकालीन रूप देते हुए नागरिक देवो भव के रूप में स्थापित किया जाए। यह केवल एक नारा नहीं,बल्कि शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन का दर्शन है। जब तक शासन के केंद्र में नागरिक नहीं होगा,तब तक विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। यह मंत्र केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था के मूल चरित्र में आमूल–चूल परिवर्तन का आह्वान है।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

2 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान दिया गया संदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।वर्तमान समय में जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है तब भ्रष्टाचार इस यात्रा का सबसे बड़ा अवरोध बनकर सामने आता है।इसलिए यह समय की मांग है कि जैसे नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया,वैसे ही भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए भी एक ठोस और समयबद्ध रणनीति अपनाई जाए। जिसकी मांग मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हर आर्टिकल के माध्यम से करते रहता हूं आज फिर इस आर्टिकल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है,यह सामाजिक विश्वास का हनन है। यह उस तंत्र को खोखला करता है, जिसपर लोकतंत्र टिका होता है। विकसित भारत के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध यदि हम ईमानदारी से आत्ममंथन करें,तो पाएंगे कि भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार है। यह केवल आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि सामाजिक विश्वास, प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो व्यवस्था को भीतर से खोखला कर देती है। चाहे वह एक छोटे स्तर का कर्मचारी हो या उच्च पदस्थ अधिकारी जब तक काम निकालने की मानसिकता और जुगाड़ संस्कृति समाज में बनी रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं।जब एक आम नागरिक सरकारी दफ्तर में जाता है,तो वह केवल एक सेवा की अपेक्षा नहीं करता,बल्कि वह न्याय,पारदर्शिता और सम्मान की भी उम्मीद करता है। यदि उसे वहां भ्रष्टाचार,उपेक्षा या अपमान का सामना करना पड़ता है,तो उसका विश्वास न केवल उस संस्था से,बल्कि पूरे शासन तंत्र से उठने लगता है।यही कारण है कि नागरिक देवो भव की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है,क्योंकि यह शासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक सर्वोपरि है और उसकी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।

साथियों बात अगर हम नागरिक देवो भव की संकल्पना को समझने की करें तो इसका का अर्थ है,हर नागरिक को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।यह सोच प्रशासन को पावर-सेंट्रिक से पीपल-सेंट्रिक बनाती है।इस अवधारणा के अंतर्गत:सरकारी पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनता है,अधिकारी और कर्मचारी अपने रुतबे को त्यागकर सेवाभाव को अपनाते हैं, हर निर्णय में नागरिक के हित को सर्वोपरि रखा जाता हैयदि चपरासी से लेकर मंत्री तक हर व्यक्ति इस भावना को आत्मसात कर ले, तो भ्रष्टाचार का स्वतः ही अंत हो सकता है।व्यक्तिगत परिवर्तन से संस्थागत परिवर्तन तक पीएम ने अपने संबोधन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन ही संस्थागत परिवर्तन का आधार बन सकता है।यह विचार अत्यंत गहरा है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होता है, तो उसका प्रभाव पूरे संस्थान पर पड़ता है।एक ईमानदार क्लर्क पूरी फाइल प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकता है,एक जिम्मेदार अधिकारी पूरे विभाग की कार्यशैली बदल सकता हैएक संवेदनशील मंत्री नीति निर्माण को जनहितकारी बना सकता है,इस प्रकार,इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही इंस्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनता है।स्थानीय प्रशासनः सरकार का वास्तविक चेहरा आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब संसद या मंत्रालय नहीं होता, बल्कि उसका स्थानीय सरकारी कार्यालय ही सरकार का चेहरा होता है।तहसील कार्यालय नगर निगम,पुलिस स्टेशन,सरकारी अस्पताल यही वे स्थान हैं, जहां नागरिक सीधे सरकार से जुड़ता है। यदि यहां का व्यवहार सकारात्मक, पारदर्शी और संवेदनशील होगा, तो लोकतंत्र में विश्वास स्वतः ही मजबूत होगा। लेकिन यदि यहां भ्रष्टाचार, देरी और असंवेदन शीलता होगी, तो जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।कर्तव्य- प्रधान प्रशासनः अधिकार से अधिक जिम्मेदारीपीएम ने प्रशासनिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, अधिकार से अधिक कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना।भारतीय संविधान भी यही सिखाता है कि अधिकार, कर्तव्यों के निर्वहन से ही प्राप्त होते हैं।जब कोई अधिकारी हर निर्णय से पहले यह सोचता है किःयह निर्णय जनता के लिए कितना लाभकारी है? इससे कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा?तो उसके निर्णय स्वतः ही अधिक प्रभावी और सटीक रूप से अति जनहितकारी बन जाते हैं।

साथियों बात अगर हरशासकीय कर्मचारी द्वारा इस भाव की संकल्पना को समझने की करें तो,हम आज आवश्यकता है कि चपरासी से लेकर उच्चतम अधिकारी तक,संत्री से लेकर मंत्री तक,हर शासकीय कर्मचारी इस भावना को अपने भीतर आत्मसत करे। पद का अहंकार छोड़कर सेवा का भाव अपनाना ही इस परिवर्तन की कुंजी है। जब एक अधिकारी अपने पद को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।यह व्यक्तिगत परिवर्तन ही संस्थागत परिवर्तन का आधार बनता है। यदि हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि उसके एक निर्णय से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा,तो वह निर्णय अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी होगा।

साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में भारत की करें तो, भारत एक आकांक्षी समाज के रूप में उभर रहा है, जहां हर नागरिक के अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं। इन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी केवल नागरिक की नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र की भी है। जब सरकार और नागरिक के बीच विश्वास का संबंध मजबूत होता है, तभी विकास की गति तेज होती है।इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था अधिकसंवेदनशील उत्तरदायी और पारदर्शी बने। नागरिक देवो भव का सिद्धांत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन को नागरिक- केंद्रित बनाता है।इस संदर्भ में क्षमता निर्माण आयोग (कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन) और आईगोट मिशन कर्मयोगी जैसी पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है,बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति का निर्माण करना है, जहां हर सरकारी कर्मचारी एक कर्मयोगी के रूप में कार्य करे। कर्मयोगी वह होता है,जो अपने कर्तव्य को पूजा मानता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। जब यह भावना प्रशासन में विकसित होती है,तो वह केवल कार्य निष्पादन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है।प्रशासनिक सुधारों के लिए यह भी आवश्यक है कि विभागों के बीच समन्वय और संवाद को बढ़ावा दिया जाए। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न विभागों के बीच संवादहीनता के कारण योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि सभी विभाग एक साझा दृष्टिकोण और समझ के साथ कार्य करें, तो शासन अधिक प्रभावी और सटीक रूप से परिणामोन्मुखी बन सकता है।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति को समझने की करें तो, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है,बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना भी आवश्यक है।इसके लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है। यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच वर्षों तक लंबित रहती है, तो यह न केवल न्याय में देरी है,बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है।इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले की जांच के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए स्रोतों की करें तो,तकनीक का उपयोग भी भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं,और पारदर्शी डेटा प्रणाली से न केवल प्रक्रियाएं सरल होती हैं, बल्कि मानव हस्तक्षेप भी कम होता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटती हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने यह साबित किया है कि यदि सही तरीके से तकनीक का उपयोग किया जाए, तो बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सकती है और लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम नागरिक देवो भव के क्रियान्वयन की करें तो इसकी भावना को केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक फैलाना होगा।जब नागरिक स्वयं भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे,तभी यह आंदोलन व्यापक रूप ले सकेगा। इसके लिए जन जागरूकता अभियान, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक हैं। सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि दूसरों को छोटा दिखाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाया जाए। यही सिद्धांत शासन व्यवस्था पर भी लागू होता है। यदि हम अपने तंत्र को अधिक सक्षम, पारदर्शी और संवेदनशील बनाते हैं, तो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। इसके लिए निरंतर सुधार,नवाचार और सीखने की प्रवृत्ति को सटीक रूप से अपनाना होगा।

साथियों बात अगर हम गुरुवार दिनांक 2 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान दिए गए संदेश को समझने की करें तो वह इसी दिशा में एक प्रेरणास्रोत है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भव होना चाहिए और प्रत्येक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिक के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय ही सरकार का चेहरा होता है, इसलिए वहां का व्यवहार और कार्यशैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वहां पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व होगा, तो जनता का विश्वास स्वतः ही मजबूत होगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़िनागरिक देवो भव केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति है,एक ऐसी क्रांति, जो भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और नैतिक संरचना को बदल सकती है।यदिःहर अधिकारी सेवाभाव अपनाए,हर नागरिक जागरूक बने,हर निर्णय में जनहित सर्वोपरि होतो वह दिन दूर नहीं, जब भारत वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा।और तब विकसित भारत 2047 केवल एक सपना नहीं,बल्कि एक साकार वास्तविकता होगी।अंततः, यह समय है,रुतबे को त्यागने का,सेवा को अपनाने का,और 'नागरिक देवो भव' को जीवन का मूल मंत्र बनाने का।

संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी)

युद्ध कोई नहीं जीता है

अमेरिका- इज़राइल और ईरान युद्ध युद्ध जिस पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान है। सारे चैनल युद्ध पर और खबर जो दिखाई जा रही है उससे शांति नष्ट हो गई है — युद्ध ने इंसानियत के मतलब पर हज़ारों बातचीत शुरू कर दी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया ने इसे नज़रअंदाज़ करना चुना, जिससे हमें हैरानी हुई कि क्या हमने अपने आस-पास एक अंधा और असंवेदनशील सोशल बबल बना लिया है। ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी में एक महीने से ज़्यादा समय से, ईरान के शहर मिनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों और टीचरों के अलावा, कई लोग मारे गए हैं। तेहरान ने मरी हुई लड़कियों की फ़ोटो जारी की हैं।

संजय गोस्वामी

उनके दुखी माता-पिता के वीडियो और फ़ोटो मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, लेकिन हममें से कितने लोगों ने उन्हें देखने की परवाह की, ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी में एक महीने से ज़्यादा समय से, ईरान के शहर मिनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों और टीचरों के अलावा, कई लोग मारे गए हैं। 24 मार्च को, दर्जनों औरतें रोम की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले, नंगे पैर मार्च कर रही थीं। ये गाज़ा और इज़राइल की माँएँ थीं। उनके बच्चे या रिश्तेदार हमास की हिंसा और इज़राइल द्वारा लिए गए बदले के शिकार हुए थे। उनका मैसेज ज़ोरदार और साफ़ थाः इज़राइल और गाज़ा दोनों के रहने वाले खुद को आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं, और उन्हें बस शांति चाहिए। यह मार्च उन लोगों के लिए एक सबक था जो सोचते हैं कि हर इज़राइली गाज़ा को जला देना चाहता है। ये औरतें 25 मार्च को पोप लियो ङ्खढ्ढङ्क से मिलीं। पोप पहले ही शांति की अपील कर चुके थे। लेकिन क्या उन्होंने इन मांओं के कहने पर अमेरिका या यूरोप से बात की? तब से उनके रिएक्शन की कोई खबर नहीं है। इस युद्ध मेंअमेरिकी सेना, उपकरण और मध्य देश में बेस भी में खो देता हैऔर फिर कहा कि मैं असलऔर ट्रम्प ने देश से कहा युद्ध मेंअमेरिकी जीत गया हैलेकिन वास्तव में, कोई नहीं जीता है,ईरान देश को अब शांति से आपसी तालमेल से इसे खत्म करना चाहिएक्योंकि अमेरिका का युद्ध का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध में 1945में अंत में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने तक का है।द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में, 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर दो परमाणु बम गिराए। इन हवाई बमबारी में 150,000 से 246,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। ये परमाणु हथियारों का सशस्त्र संघर्ष में पहला और एकमात्र प्रयोग था। हम बौनों के ज़माने में जी रहे हैं, लीडर्स के नहीं। वर्ल्ड वॉर द्बढ्ढ से पहले और उसके ठीक बाद दुनिया ने महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे बड़े लोगों को देखा, जिनके कामों, अपीलों और दलीलों का बहुत वज़न था और दुनिया भर में उनकी गूंज सुनाई दी। उन्होंने अपनी जागृति से दुनिया को जगाए रखा और ज़िंदा रखा। उनसे प्रेरित होकर, आम लोगों ने अन्याय के खिलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाई। 8 जून, 1972 की बात है। वियतनाम के ट्रांग बांग इलाके में बच्चे अमेरिका के सपोर्ट वाले हमलों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए भाग रहे थे। नौ साल की किम फुक, वियतनाम में युद्ध से हुए भयानक हालात का उदाहरण बन गई, जब उसकी पीठ पर नेपाम के हमले में जलने के बाद, वह बिल्कुल नंगी दौड़ती हुई मारी गई। युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जिसमें जान-माल की भारी हानि, आर्थिक मंदी, बुनियादी ढांचे का विनाश और गहरा मानवीय संकट शामिल है। यह न केवल देशों की सीमाओं को बदलता है और राजनीतिक स्थिरता को बाधित करता है, बल्कि पीढ़ियों तक मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक उथल-पुथल भी छोड़ता है। युद्ध के प्रमुख परिणामों को इन बिंदुओं में समझा जा सकता हैः जन-धन की हानिः युद्ध में सैनिकों और नागरिकों की भारी मृत्यु होती है, साथ ही संपत्ति, घरों और शहरों का विनाश होता है। आर्थिक मंदी और संकटः युद्धों के कारण व्यापार बाधित होता है, मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ती है और देशों पर भारी कर्ज का बोझ पड़ता है। ऊर्जा और भोजन की आपूर्ति श्रृंखला टूट जाती है। राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तनः युद्ध के परिणामस्वरूप सरकारें गिर सकती हैं, नए राष्ट्र बन सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंध बदल जाते हैं (जैसे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यों का अंत)। शरणार्थी और विस्थापनः युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में जाने को मजबूर होते हैं। दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघातः युद्ध न केवल शारीरिक घाव देता है, बल्कि सैनिकों और नागरिकों में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं छोड़ जाता है। पर्यावरणीय क्षतिः विस्फोटों और हथियारों के उपयोग से भूमि, जल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान राम का संदेश धर्म, न्याय और करुणा की स्थापना करना था, न कि केवल विनाश। उन्होंने रावण को सुधारने का अंतिम अवसर (शांति प्रस्ताव) दिया, जो दर्शाता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। उनका मुख्य संदेश अधर्म पर धर्म की विजय और युद्ध में भी मर्यादा व नीति का पालन करना था। युद्ध में भगवान राम के संदेश के मुख्य बिंदुः धर्म और न्याय की सर्वोच्चताः राम का युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। शांति का प्रयासः उन्होंने अंगद को शांति प्रस्ताव के साथ भेजा, यह स्पष्ट करने के लिए कि युद्ध से पहले हर संभव समाधान तलाशा जाना चाहिए। मर्यादा और नैतिकताः युद्ध के दौरान भी, उन्होंने नियमों का पालन किया और पराजित या निहत्थे शत्रु पर प्रहार न करने जैसी मर्यादाओं का पालन किया। समावेशिताः उन्होंने वनवासियों, वानरों और सभी जातियों को साथ लेकर यह संदेश दिया कि न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एकता आवश्यक है। शत्रु के प्रति सम्मानः रावण के वध के बाद, राम ने विभीषण से कहा कि शत्रु के मरणोपरांत बैर समाप्त हो जाता है और रावण को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिलाया। अहंकार का नाशः राम ने रावण के माध्यम से यह संदेश दिया कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार ही विनाश का कारण बनते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

नाइट विजन, एआई आधारित ड्रोन से विंध्याचल धाम की सुरक्षा; अवैध गतिविधियों का पता चल सकेगा

मिर्जापुर, एजेंसी। मां विंध्यवासिनी मंदिर और विंध्यधाम की सुरक्षा अब नाइट विजन, इंफ्रा रेड सेंसर और एआई आधारित ड्रोन कैमरे से की जाएगी। इससे अब रात में धाम के अलावा पूरे विंध्य पहाड़ी क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी। इससे रात को पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही अवैध गतिविधियों का भी पता चल सकेगा। वहां पर पुलिस समय पर पहुंच कर स्थिति नियंत्रित करेगी।यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने दी। उन्होंने आगे कहा कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। चैत्र नवरात्र में ही यहां 47 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बृहद प्रस्ताव का यह हिस्सा है।

रखी जाएगी नजर: एसपी ने आगे बताया कि शासन से विंध्याचल मंदिर और धाम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मिर्जापुर पुलिस को दो नाइट विजन, इंफ्रा रेड सेंसर और एआई आधारित दो ड्रोन कैमरे मिले है। इन सामानों की लागत 17 लाख रुपये आई है। इसके अलावा भी 202 कैमरे मंगवाए गए हैं। इस ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इससे अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। रात में विंध्याचल के घने जंगलों को स्कैन करने के लिए लो लाइट सेंसर और एनआईआर सहायक लाइट ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर लगा है। इससे एकांत क्षेत्र में तापमान का पता चल जाएगा। आग लगने की घटना का पता लगाकर उसे रोका जा सकेगा।

एआई आधारित ड्रोन से होगी निगरानी: ड्रोन वास्तविक समय में भीड़ का आकलन कर लेगा। एआई आधारित होने पर स्मार्ट ट्रैक तकनीक का उपयोग कर भीड़ में ही विशिष्ट व्यक्ति या कार का पता लाया जा सकेगा। मंदिर के आस-पास पहाड़ी क्षेत्र में जहां गुफाएं आदि हैं। जहां पुलिस का पहुंचना मुश्किल है। वहां पर ड्रोन निगरानी कर पुलिस का मार्गदर्शन करेगा। उन्नत थर्मल इमेजिंग क्षमता वाले ड्रोन कैमरे से एकांत, अंधेरे, वन क्षेत्र, नदी और तटों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इससे संभावित अवैध गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी। एआई से इसकी फोटो आदि फीड कर कमांड देंगे तो भीड़ में छिपे अपराधी या वाहन का पीछा किया जा सकेगा। यातायात प्रबंधन में ड्रोन कैमरा काम आएगा।

जंगल के रास्ते होने वाली तस्करी पर ड्रोन रखेगा नजर: क्षेत्र के अहरौरा और चुनार आदि क्षेत्र में जंगल के रास्ते होने वाली पशु तस्करी को भी ड्रोन की मदद से रोका जा सकेगा। पशु तस्कर रात में जंगल के रास्ते हांक कर मवेशी ले जाते हैं। एआई की मदद से जंगल के रास्ते जाने वाल तस्करी के पशुओं को ड्रोन पहचान कर सूचना देगा। इसे तस्करों को ट्रैक कर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

नाइट विजन, हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल इमेजिंग क्षमता वाले एआई आधारित ड्रोन कैमरा रात में मां विंध्यवासिनी धाम के अलावा पूरे पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी करने में मदद करेगा। ऐसे दो ड्रोन मिले हैं। मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रदेश का पहला मंदिर होगा। जहां नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जंगल के रास्ते पशु तस्करी और यातायात प्रबंधन में ड्रोन काम आएगा। - अपर्णा रजत कौशिक, एसपी

कानपुर के नर्सिंगहोम में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट दो का था प्लान पर एक हुआ

कानपुर, एजेंसी। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट प्रकरण में शहर के बड़े और नामी नर्सिंगहोम का नाम सामने आया है। यहां कुछ दिन पहले ही गुर्दा प्रत्यारोपित हुआ था। यह जानकारी पुलिस को गुरुवार को गिरफ्तार हुए ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार से पूछताछ में हुई है। दोनों ने अधिकारियों को बताया है कि यह नर्सिंगहोम रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक बना हुआ है। रोजाना काफी संख्या में मरीज आते हैं।कई छोटे-बड़े ऑपरेशन भी होते हैं। पुलिस ने नर्सिंगहोम के दो स्टाफ को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार दोनों ओटी टेक्नीशियन हैं। राजेश कुमार का प्रमोशन हो गया है। उसे ओटी मैनेजर बना दिया गया है। उसका वेतन 70 हजार महीना है जबकि कुलदीप को 42 हजार रुपये मिलते हैं। दोनों डॉ. रोहित के संपर्क में थे। डॉ. रोहित एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं।

एनसीआर ही नहीं कई क्षेत्रों में फैला हुआ है नेटवर्क: उसका संबंध सर्जन डॉ. अली और डॉ. सैफ के साथ में है। दोनों ने पैरामेडिकल स्टाफ अखिलेश और शैलेश के बारे में भी बताया है। ये सभी गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। ये कई बार शहर आ चुके हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगा दी गई हैं। क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच की टीमें भी सक्रिय हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े आरोपियों का नेटवर्क सिर्फ एनसीआर ही नहीं कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

डॉक्टरों की टीम करने आई थी दो ट्रांसप्लांट: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि डॉक्टरों की दोनों टीम रविवार देर रात दो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आई थी, लेकिन एक ही करके चली गई थी। यह जानकारी दोनों ओटी टेक्नीशियन ने पूछताछ में दी है। दोनों ने झारखंड और नेपाल के दो डोनरों की जानकारी दी है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लग गई हैं। जिस रोगी को किडनी लगानी थी, वह भी शहर के नर्सिंगहोम में उपचाराधीन है। शुक्रवार को उनके परिजनों से जानकारी जुटाई जाएगी।

मामले में दो ओटी टेक्नीशियन हुए हैं गिरफ्तार: आहूजा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एनसीआर क्षेत्र से यूरोलॉजिस्ट और दो ओटी टेक्नीशियन आए थे। रावतपुर पुलिस ने गुरुवार को गाजियाबाद के राजेश कुमार और हापुड़ के कुलदीप सिंह राघव को दहलन क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया जबकि यूरोलॉजी के सर्जन की तलाश जारी है। राजेश कुमार नोएडा के सर्वोदय हॉस्पिटल और कुलदीप सिंह राघव गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शांति गोपाल नर्सिंगहोम में ओटी टेक्नीशियन हैं।दोनों से टीम में शामिल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी की गई। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। डीसीपी पश्चिम एमएम कासिम आबिदी ने बताया कि रविवार देर रात आहूजा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। यहां बिहार के बेगूसराय के आयुष की एक किडनी मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर को लगाई गई थी। सर्जरी के बाद एक टीम रेलबाजार क्षेत्र से बुक हुई किया कैरेंस कार से गाजियाबाद के वैशाली तक गई।कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को छोड़कर लौट आई। पुलिस ने जानकारी जुटाकर दोनों ओटी टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया।

वाराणसी में तीन नई टाउनशिप बनाएगा वीडीए, 1700 करोड़ रुपये होंगे खर्च; बजट प्रस्तावित

वाराणसी, एजेंसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार परिचालन से 2,070.61 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 448 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, 2,069.07 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 343 प्रतिशत अधिक है।

अफसरों ने शासन को भेजी रिपोर्ट: उन्होंने बताया कि वीडीए की स्थापना 19 अगस्त 1974 को वाराणसी के सुनियोजित एवं समग्र विकास के उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में इसका अधिकार क्षेत्र लगभग 793 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें महापालिका क्षेत्र सहित 635 गांव शामिल थे। वर्ष 2024 में नगर क्षेत्र के विस्तार को स्वीकृति मिलने के बाद 215 नए राजस्व ग्रामों को भी वीडीए के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। इसके फलस्वरूप वर्तमान में इसका कुल विकास क्षेत्र बढ़कर 1,073 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

वीडीए का कार्यक्षेत्र पवित्र गंगा नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत है, जो इसे भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से दो भागों में विभाजित करता है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का सतत, संतुलित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है।

शहर के नियोजित विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगा: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण के स्वीकृत पुनरीक्षित बजट में लगभग 378 करोड़ की आय तथा 467.50 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में वीडीए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत चार बड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति एवं परियोजना विकास की कार्यवाही कर रहा है।

बजट शहर के नियोजित विकास को देगी नई दिशा : यह बजट वाराणसी के तेजी से हो रहे शहरी विस्तार, नई आवासीय टाउनशिप, संस्थागत विकास तथा जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वीडीए की ओर से प्रस्तावित यह बजट आने वाले समय में शहर के नियोजित विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर के समग्र विकास का प्रमुख स्तंभ है और इसकी योजनाबद्ध गतिविधियां वाराणसी को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और समृद्ध शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

संस्कृत शिक्षा परिषद को मिलेगा अपना भवन 25 साल का इंतजार खत्म

लखनऊ, एजेंसी। यह बिल्डिंग नागर शैली में बनेगी। यहां पर प्रशासनिक केंद्र के साथ-साथ संस्कृत के शोध और विस्तार को भी गति मिलेगी। इमारत के लिए बजट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद व निदेशालय को 25 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना नियमित ठिकाना मिलेगा। राजधानी में राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज के पीछे स्थित खाली जमीन पर परिषद व निदेशालय का संयुक्त चार मंजिला भवन का निर्माण होगा। शासन ने इसके ए 42 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की पढ़ाई व प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी संस्कृत शिक्षा निदेशालय पास की ओर से की जाती है। जबकि परीक्षा व परिणाम परिषद की ओर से जारी किया जाता है। पूर्व में यह केजीएमयू के स्थित बिल्डिंग से इसका संचालन होता था। किंतु इसके जर्जर होने के बाद इसे सीटीई में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर जगह कम पड़ रही थी।इस क्रम में शासन ने संस्कृत शिक्षा निदेशालय व परिषद के लिए एक संयुक्त बिल्डिंग तैयार करने का निर्णय लिया था। इसके लिए आवश्यक औपचारिकता पूरी कर बजट भी जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह बिल्डिंग नागर शैली में बनेगी। यहां पर प्रशासनिक केंद्र के साथ-साथ संस्कृत के शोध और विस्तार को भी गति मिलेगी।

पांडुलिपियां और प्राचीन ग्रंथ भी रखे जाएंगे: यहां पर लैंग्वेज लैब के साथ ही लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल आदि की सुविधा होगी। यहां पर संस्कृत से जुड़ी पांडुलिपियां आदि प्राचीन ग्रंथ भी रखे जाएंगे। पूर्व में यह भवन सिटी स्टेशन के पास प्रस्तावित था लेकिन वहां से दूसरे चरण की मेट्रो जाने के प्रस्ताव को देखते हुए निशातगंज में इसके भवन निर्माण का निर्णय लिया गया था।

रफ्तार का कहर...इकलौते बेटे की मौत, पत्नी और माता-पिता बेसुध

मऊ, एजेंसी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 269 किलोमीटर पॉइंट की सर्विस लेन पर सड़क हादसे में युवक की मौत की सूचना मिलते ही मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक की पहचान की गई। परिजनों में इस हादसे के बाद कोहराम मच गया था।

जानकारी के अनुसार रानीपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह बृहस्पतिवार की शाम किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुहम्मदाबाद गोहना गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय रात करीब 11 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 269 किलोमीटर पॉइंट की सर्विस लेन पर भाटीकला गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

परिजनों में मचा कोहराम: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धर्मेंद्र की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पुलिया से जा टकराई। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी।घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक धर्मेंद्र अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके परिवार में वृद्ध माता-पिता, पत्नी के अलावा तीन वर्ष की एक बेटी और आठ माह का मासूम बेटा है।

यूपी के 8 जिलों के 20 लाख जनधन खातों में एक पैसा नहीं

बैंकों ने इन खातों को संदिग्ध श्रेणी में डाला

लखनऊ, एजेंसी। राज्य सरकार को भेजी गई जनधन खातों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी में कुल जनधन खातों की संख्या 10.22 करोड़ है। वहीं, देश में 57.58 करोड़ खाते हैं।

उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में खोले गए 20 लाख जनधन खातों में एक भी पैसा नहीं है। इनमें चार जिले पूर्वांचल और चार पश्चिमी यूपी के हैं। इनमें महिलाओं के खाते पुरुषों से ज्यादा हैं। ये खाते बैंकों के लिए बोझ बन गए हैं क्योंकि इन्हें सक्रिय रखने के लिए बैंकों को सालाना 700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं, बैंकों ने शून्य बैलेंस वाले इन खातों को मनी म्यूल अकाउंट के रूप में संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया

है।बैंकों की ओर से राज्य सरकार को भेजी गई जनधन खातों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी में कुल जनधन खातों की संख्या 10.22 करोड़ है। वहीं, देश में 57.58 करोड़ खाते हैं। इस लिहाज से यूपी की हिस्सेदारी करीब 18त है, जो देश में सर्वाधिक है। इनमें 53त महिला खाताधारक हैं और इनमें 58 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा है। पूर्वांचल और पश्चिमांचल के आठ जिलों में 1.60 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं। इन्हीं में 20 लाख खातों का बैलेंस शून्य है। शेष खातों में करीब 7800 करोड़ रुपये जमा हैं।

सालाना खर्च हो रहे 700 करोड़: एक जनधन खाते को सक्रिय और व्यवस्थित रखने के लिए बैंकों को हर साल लगभग 3500 रुपये तक का खर्च उठाना पड़ता है। इस खर्च में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों का वेतन और शाखा का रखरखाव शामिल है। इस तरह अकेले इन 8 जिलों के खाली खातों को मेनटेन रखने में ही बैंकों को हर साल 700 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ रहा है।मनी म्यूल अकाउंट : बैंक खाली या निष्क्रिय जनधन खातों को मनी म्यूल के रूप में संदिग्ध इसलिए मानते हैं क्योंकि इनका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध धन को सफेद करने या साइबर ठगी के पैसे को घुमाने के लिए किया जा सकता है।

अब छोटे और पिछड़े जिलों में खुलेंगे बड़े औद्योगिक केंद्र, स्थानीय उत्पादों वाले उद्योगों को बढ़ाया जाएगा

लखनऊ, एजेंसी। नई रणनीति के तहत औद्योगिक विकास को संतुलित करने की कवायद की जा रही है। इससे हाथरस-बाराबंकी समेत कई अन्य जिलों को फायदा मिलेगा।उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए छोटे व पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की रणनीति बनाई गई है। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने बलिया, हाथरस, फतेहपुर, बाराबंकी और चित्रकूट जैसे जिलों में बड़े औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए हालिया फैसलों के साथ पहले के निर्णयों को भी जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है।ओडीओपी योजना के जरिये स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम हो रहा है। यूपीसीडा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में कई छोटे जिलों में मिनी औद्योगिक एस्टेट और फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजनाओं को विस्तार देते हुए बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि बलिया, हाथरस, फतेहपुर, बाराबंकी और चित्रकूट के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए कुछ शर्तों में ढील दी गई है। तलपट (लेआउट) मानचित्रों में संशोधन के निर्देश देते हुए उन्हें स्वीकृति दे दी गई है।

इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। पहले से बंद औद्योगिक इकाइयों और कताई मिलों की जमीन के पुनः उपयोग में लाने का फैसला भी लागू करना शुरू कर दिया गया है।बड़े शहरों पर औद्योगिक दबाव कम करने की रणनीति : छोटे जिलों में उद्योग स्थापित करने से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि बड़े शहरों पर बढ़ता औद्योगिक दबाव भी कम होगा। यही नहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में निवेश का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा।

सरकारी अस्पतालों में बंद पड़े हैं 65 वेंटिलेटर, एक से दूसरे हॉस्पिटल की दौड़ में जान गवां रहे मरीज

लखनऊ, एजेंसी। राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर विशेषज्ञ और मैनपावर के अभाव में बंद पड़े हैं। ऐसे में गंभीर मरीज वेंटिलेटर के लिए एक से दूसरे अस्पताल के बीच दौड़ लगाने में अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं, पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में मरीजों का दबाव ज्यादा होने से समस्या है।

गोरखपुर से रेफर होकर लखनऊ आए देवरिया के एक मरीज को समय से वेंटिलेटर नहीं मिल सका। नतीजा, बुधवार को उसकी जान चली गई। यह घटना राजधानी के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। जानकारों का कहना है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर विशेषज्ञ और मैनपावर के अभाव में बंद पड़े हैं। ऐसे में गंभीर मरीज वेंटिलेटर के लिए एक से दूसरे अस्पताल के बीच दौड़ लगाने में अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों की सेहत पर

फर्क नहीं पड़ रहा है। वह आंख बंद किए बैठे हैं।लोकबंधु अस्पताल 300 बेड की क्षमता का अस्पताल है। यहां पर 40 वेंटिलेटर हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर पर मरीजों की भर्ती हो रही है, बाकी बंद पड़े हैं। इसकी वजह यह है कि बीते वर्ष हुए अग्निकांड के बाद आईसीयू का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इससे सीमित वेंटिलेटर पर मरीजों की भर्ती हो रही है।बलरामपुर अस्पताल में 60 वेंटिलेटर बेड हैं जिसमें 28 ही का संचालन हो रहा है। मैनपावर व विशेषज्ञों का संकट होने की वजह से पूरी क्षमता संग वेंटिलेटरों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है।ठाकुरगंज में दो व रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में पांच वेंटिलेटर हैं। इन पर मरीजों की नियमित रूप से भर्ती नहीं हो पा रही है।

विशेषज्ञ डॉक्टर व संसाधनों की कमी के लिए सभी वेंटिलेटर बेड का संचालन नहीं हो पा रहा है।

चिकित्सा संस्थानों का हालः पीजीआई समेत दूसरे मेडिकल संस्थानों में करीब 500 वेंटिलेटर हैं। यहां लगभग पूरे प्रदेश और बिहार के भी मरीज आते हैं।

आईआईटी बीएच की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म...जिरह टली

अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को

ये हैं सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी

वाराणसी , एजेंसी। बताया गया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण दोपहर बाद वकीलों ने शोकवश कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। इसके चलते विवेचक से बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की जा सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता मौजूद रहे। वहीं, आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ताओं को विवेचक से जिरह करनी थी, लेकिन वकीलों के कार्य से विरत रहने के कारण यह प्रक्रिया टल गई। एक अन्य आरोपी आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे।अभियोजन के अनुसार, 2 नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल को आरोपी के रूप में नामजद किया।मामले में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का मुख्य बयान पहले ही अदालत में दर्ज किया जा चुका है।

काशी में विक्रमादित्य का महानाट्य: 3 मंच, 18 घोड़े, 2 रथ...होगा सजीव चित्रण

सीएम मोहन अर्पित करेंगे वैदिक घड़ी

वाराणसी, एजेंसी। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न कालिदास, वराहमिहिर सहित अन्य विद्वानों की विद्वता का भी सजीव चित्रण होगा। बाएं मंच पर महाकाल मंदिर की भव्य संरचना और 8 फीट के शिवलिंग पर दिव्य भस्म आरती का दृश्य मुख्य आकर्षण होगा।

बरेका में शुक्रवार से शुरू हो रहे सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य में 200 से अधिक कलाकार हाथी, घोड़े, रथ और पालकियों के साथ उपस्थित होंगे। इसमें भव्य युद्ध, लाइट शो, आतिशबाजी, नृत्य और बाबा महाकाल की भस्म आरती की दिव्य झलकियां शामिल होंगी। तीन भव्य मंचों पर 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी के साथ जीवंत प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य अतिथि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम मोहन यादव महानाट्य का शुभारंभ करेंगे।

महानाट्य का होगा सजीव चित्रण। - फोटो : संवाद: केंद्र में

80म62 का मुख्य मंच और दोनों ओर 42म42 के लेफ्ट और राइट मंच तैयार किए गए हैं। इन मंचों पर सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और भविष्य पुराण के प्रसंगों के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के अद्वितीय व्यक्तित्व, सुशासन और न्यायप्रियता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। बाबा महाकाल की भस्म आरती की दिव्य झलकियां शामिल होंगी। - फोटो : संवादमहानाट्य को और अधिक जीवंत बनाने के लिए 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी के साथ भव्य प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मंचीय प्रभाव को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक ग्राफिक्स, 400 से अधिक लाइट्स, 80म32 की एलईडी स्क्रीन और दो बार भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, जो दर्शकों को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। 10 से 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। - फोटो : संवाद: बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे विक्रमादित्य वैदिक घड़ीमहाकाल की नगरी उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को यह घड़ी अर्पित करेंगे। भारत में भारतीय काल गणना पर आधारित यह पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में किया था। यह घड़ी वैदिक काल गणना के समस्त घटकों के आधार पर बनाई गई है। यह सूर्योदय से काम करती है, इसलिए जिस स्थान पर सूर्योदय का समय होगा, उस स्थान की काल गणना उसी के अनुसार होगी। इस घड़ी के माध्यम से वैदिक समय, लोकेशन, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय पंचांग, विक्रम संवत मास, ग्रह स्थिति, भद्रा स्थिति और चंद्र स्थिति आदि की जानकारी उपलब्ध है।

मानेसर नगर निगम का बड़ा कदम, सड़कों किनारे टाइल्स लगाकर धूल मुक्त करेंगे शहर

मानेसर, एजेंसी। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सड़कों किनारे धूल दिखाई नहीं देगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा सड़कों किनारे इंटरलाकिंग टाइल लगाई जाएंगी। नगर निगम मानेसर द्वारा 19 सड़कों के दोनों तरफ फूटपाथ बनाने और टाइल्स लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए नगर निगम की वित्त एवं संविदा समिति की मंजूरी मिल चुकी है। सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए करीब 47 करोड़ रुपये नगर निगम द्वारा खर्च किए जाएंगे। तारकोल से बनी सड़कों को किनारे से पक्का किया जाएगा। कहीं भी धूल एकत्रित न हो इसके लिए यह कदम उठाए गए हैं। धूल उड़ने से लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की द्वारा कराए गए सर्वे के बाद नगर निगम को की गई सिफारिश पर यह कार्य किया जाएगा। पिछले वर्ष मानेसर का प्रदूषण स्तर पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था। इससे पूरे देश में किरकिरी हुई थी। इन कार्यों के

लिए नगर निगम द्वारा वित्तीय मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद कार्य शुरू होगा। नगर निगम के एक्सईएन मनदीप धनखड़ का कहना है कि सड़कों किनारे टाइल लगाने के कार्यों को लेकर जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इन सड़कों किनारे लगाई जाएंगी टाइल : नगर निगम की डिवीजन एक के नौ और डिवीजन दो की दस सड़कों किनारे टाइल्स लगाकर पक्का किया जाएगा। डिवीजन एक में हयातपुर से गांव गढ़ी की सड़क निर्माण पर एक करोड़ 54 लाख, शिकोहपुर गांव में मुख्य सड़क के निर्माण पर 2 करोड़ 82 लाख रुपये, गांव भांगरौला से बास रोड़ के निर्माण पर 2 करोड़ 82 लाख रुपये, पटौदी रोड़ से ढ़ोरका में डेढ़ किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, गांव गढ़ी से हरसरू में सड़क, फुटपाथ व नाले के निर्माण पर 2 करोड़ 88 लाख रुपये, गांव बामड़ौली की मुख्य सड़क के बचे हुए कार्यों पर एक करोड़ 43 लाख रुपये, पटौदी रोड़ से गांव मेवका तक सड़क निर्माण पर 4 करोड़ 56 लाख रुपये, गांव हयातपुर से ढाणा रोड़ के निर्माण पर 5 करोड़ 21 लाख रुपये, गांव हयातपुर स्थित किडजी स्कूल से गांव नवादा के नयाशा पेट्रोल पंप तक सड़क निर्माण पर एक करोड़ 22 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसी प्रकार डिवीजन दो में एनएच 48 से गांव नैनवाल तक सड़क निर्माण पर एक करोड़ 5 लाख रुपये, कोटा खंडेवला से गांव बार गुर्जर तक सड़क निर्माण पर एक करोड़ 13 लाख रुपये, गांव बार गुर्जर से बाबा मोहन राम मंदिर तक सड़क निर्माण पर एक करोड़ 17 लाख रुपये, गांव नैनवाल से खाती ढ़ाणी और मुंशी ढ़ाणी तक सड़क निर्माण पर एक करोड़ 19 लाख रुपये खर्च होंगे।

वहींकोटा खंडेवला से गांव बार गुर्जर के बाबा मोहन राम मंदिर तक सड़क निर्माण पर 1 करोड़ 72 लाख रुपये, गांव कोटा खंडेवला से गांव नौरंगपुर जाने वाले रास्ते के निर्माण पर 6 करोड़ 40 लाख रुपये, एनएच 48 से सहरावन गांव तक सड़क का निर्माण 2 करोड़ 22 लाख रुपये में होगा। इसी प्रकार एनएच 48 से गांव कुकड़ौला की सड़क निर्माण पर एक करोड़ 81 लाख रुपये, एनएच 48 स्थित रामपुरा चौक से गांव नखड़ौला जाने वाले रास्ते के निर्माण पर एक करोड़ 32 लाख रुपये और गांव मानेसर को कासन स्थित पूरण भगत मंदिर से जोड़ने वाले मुख्य रास्ते के निर्माण पर नगर निगम मानेसर 2 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च होंगे।

दिल्ली के नवीन शाहदरा में आवारा कुत्तों का आतंक, लोग घरों में कैद; आंखें मूंदे बैठे निगम के अधिकारी

पूर्वी दिल्ली, एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के नवीन शाहदरा स्थित एल और जे ब्लाक में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से लगातार कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बीते एक माह में ही करीब पांच लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है, जिससे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। सुनील जैन ने बताया कि गली में रोजाना 10 से 12 आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जो अचानक राहगीरों और बच्चों पर हमला कर देते हैं। खासकर सुबह और शाम के समय स्थिति अधिक खतरनाक हो जाती है। बच्चों का स्कूल जाना और नौकरीपेशा लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। निवासियों ने इस समस्या को लेकर निगम में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद निगम की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। निवासियों ने जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। उधर, पार्षद रितेश सूजी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के चलते कुत्तों को पकड़ा नहीं जा सकता। कुत्तों की नसबंदी का काम लगातार जारी है। यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-2 में आवारा कुत्तों का आतंक, एक महीने में 10 लोग हुए शिकार; कब जागेगा प्राधिकरण? आवारा कुत्ते की वजह से अकेले घर से बाहर नही निकल सकते। घरेलू सहायिका पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने से आस-पास के लोग काफी परेशान है। - मंजु गुप्ता निगम से कई बार शिकायत के बाद भी समाधान नही निकला। पार्षद को भी समस्या के बारे में अवगत कराया परंतु उन्होंने आश्वासन देकर लौटा दिया। बच्चे घर के बाहर खेलने से डरने लगे है। कई बार तो हाथ से खाने पीने का सामान भी झपट लेते है। निगम अधिकारियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द समस्या से मुक्ति दिलाई जाए।

300 करोड़ में बनेंगी सड़कें, सिग्नेचर सिटी में बनेगा नया फायर स्टेशन

गाजियाबाद, एजेंसी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नए विकास कार्य भी जल्द शुरू होंगे। गाजियाबाद जिले में 300 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा और लोनी स्थिति ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में फायर स्टेशन बनाया जाएगा। फायर स्टेशन बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में ये जानकारी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों ने सीडीओ को दी। बैठक में साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा रुपये लेकर सरकारी जमीन पर मीट की दुकानें खुलवाने और कबाड़ खरीदने खुलवाने की शिकायत की गई, इस पर सीडीओ ने संबंधित के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। विकास से जुड़े जो निर्माण कार्य अधूरे हैं, उनको जल्द पूरा किया जाए।

शरीर और मन दोनों को संतुलन प्रदान करता है वृक्षासन

नई दिल्ली , एजेंसी। तनाव भरी जीवनशैली में मानसिक शांति के लिए योग को प्रभावी उपाय माना जाता है। योगासनों में वृक्षासन एक ऐसा अभ्यास है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलन प्रदान करने में मदद करता है। संस्कृत शब्द 'वृक्ष' का अर्थ पेड़ होता है और इस आसन का नाम भी उसी से लिया गया है।

जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों के सहारे मजबूती से खड़ा रहता है और तेज हवा या बारिश में भी स्थिर बना रहता है, उसी प्रकार यह आसन व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के बीच भी शांत और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्षासन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने वाला एक प्रभावी योगासन है। इसे एक पैर पर खड़े होकर नमस्कार मुद्रा में किया जाता है, जिससे शरीर की स्थिरता और संतुलन क्षमता

विकसित होती है। नियमित अभ्यास से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन धीरे-धीरे बेहतर होने लगता है।

इसके साथ ही यह आसन ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। आयुष मंत्रालय के अनुसार वृक्षासन एक संतुलनकारी योगाभ्यास है, जो मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और शारीरिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। इसका नियमित अभ्यास रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पैरों की मांसपेशियों को टोन करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा यह शरीर के 'न्यूरो-मस्कुलर को-ऑर्डिनेशन' को बेहतर बनाकर शरीर और दिमाग के बीच तालमेल को मजबूत करता है। योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह आसन वात दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है और तनाव को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।

योग विशेषज्ञ बताते हैं कि इस आसन का अभ्यास सुबह खाली पेट करना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। सुबह के समय शरीर और मन दोनों अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, जिससे आसन का प्रभाव बेहतर तरीके से मिलता है।

हालांकि यदि समय की कमी के कारण इसे शाम के समय करना हो तो भोजन के कम से कम चार से छह घंटे बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि वृक्षासन करने से पहले शरीर को तैयार करने के लिए कुछ अन्य योगासन करना उपयोगी होता है। इनमें त्रिकोणासन, वीरभद्रासन और बद्ध कोणासन शामिल हैं, जो शरीर को लचीला बनाने और संतुलन सुधारने में मदद करते हैं।

फरीदाबाद में फिर बादल छाने से किसान परेशान, गेहूं कटाई के बीच गुणवत्ता खराब और मंडी में भाव भी घटे

फरीदाबाद, एजेंसी। दो दिन के बाद फिर से आसमान में घने बादल छाए होने और ठंडी हवा चलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसल कटाई का काम जोरों से चल रहा है। मंडी में भी फसल की आवक पूरे जोर पर है। यदि वर्षा हो गई तो कटाई का काम रुक जाएगा। गेहूं की गुणवत्ता इस बार पहले से ही खराब हो चुकी है। दाना पतला पड़ गया है और काला दिखाई दे रहा है। मंडी में किसानों से लस्टर लास के नाम पर एक कुंतल गेहूं पर डेढ़ किलो अतिरिक्त गेहूं लिया जा रहा है। हालांकि सरकार समर्थन मूल्य पर 2585 रुपये प्रति कुंतल खरीद रही है। जबकि व्यापारी इस फसल को 2350 से 2400 रुपया प्रति कुंतल खरीद रहे हैं। किसान फसल को हार्वेस्टर से ज्यादा काटने में लगे हुए हैं। ताकि जल्दी फसल कट कर घर और मंडी पहुंच जाए।

रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत होगी दूर

गुरुग्राम में पीएनजी कनेक्शन में तेजी

गुरुग्राम, एजेंसी। रसोई गैस सिलिंडरों की किल्लत से जूझ रहे शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद गुरुग्राम नगर निगम ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को सर्वे और अन्य कागजी औपचारिकताओं से छूट दे दी है। इस फैसले के बाद निगम ने तेजी दिखाते हुए कई आवेदनों पर 24 घंटे के भीतर ही लेटर आफ इंटेंट (एलओआइ) जारी कर दिए हैं, जिससे परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम द्वारा विभिन्न निजी और सरकारी गैस वितरण कंपनियों को करीब 45 किलोमीटर से अधिक लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति प्रदान की गई है। एलओआइ जारी होने के साथ ही अब संबंधित एजेंसियां चिह्नित क्षेत्रों में जल्द ही खोदाई और पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगी। योजना के तहत कार्य पूरा होते ही शहर के हजारों घरों तक सीधे पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचने लगेगी, जिससे सिलिंडरों पर निर्भरता कम होगी।

योजना के पहले चरण में एक एजेंसी को हंस एंकलेव और सेक्टर-33 के आसपास लगभग दस किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शहर के अन्य कई रिहायशी इलाकों में भी पीएनजी नेटवर्क विस्तार की मंजूरी दी गई है। निगम का दावा है कि जिन क्षेत्रों में कार्य शुरू होगा, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा में 15 अप्रैल से गंगाजल की सप्लाई शुरू

पाइपलाइन रिपेयरिंग अंतिम चरण में

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 15 अप्रैल के बाद गंगाजल की आपूर्ति शुरू होगी। तिलपता फ्लाईओवर के पास एक जगह मुख्य पाइपलाइन टूट गई है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल ग्रेनो वेस्ट में भूजल की आपूर्ति की जा रही है। पेयजल की आपूर्ति में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पाइपलाइन की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्राधिकरण के मुताबिक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) पर तिलपता फ्लाईओवर के पास गंगाजल की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। यहां पर नाले का निर्माण किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में पाइप लाइन दुरुस्त कर दी जाएगी। इसके बाद ट्रायल किया जाएगा। ऐसे में 15 अप्रैल के बाद गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो सकेगी। शुरुआत में भूजल के साथ 40-50 प्रतिशत गंगाजल मिलाकर आपूर्ति की जाएगी। निर्माणाधीन चार भूमिगत जलाशय का काम अगले कुछ महीने में पूरा होने के बाद गंगाजल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा ईस्ट के सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा, स्वर्णनगरी पीथ्री, पी फोर सहित अधिकतर सेक्टरों में भूजल कें साथ मिलाकर गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा ने बताया कि चार मूर्ति तक गंगाजल पहुंच गया है। मुख्य पाइप लाइन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। उम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अन्य हिस्सों

गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। गंगाजल शुरू होने से सोसायटी निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा ईस्ट व वेस्ट में लगभग 270 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसमें 70-80 एमएलडी गंगाजल शामिल है।

उम्र के आधार पर तय होगा नाबालिग सोशल मीडिया पर सक्रिए रहेंगे या नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार बच्चों और किशोरों द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और उससे जुड़े जोखिमों को देखते हुए नए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय एक ऐसा संतुलित मॉडल विकसित करना है, जिसमें उम्र के आधार पर अलग-अलग स्तर की पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस महत्वपूर्ण विषय पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा का दौर जारी है। प्रस्तावित नियमों के तहत मुख्य रूप से पेरेंटल कंट्रोल यानी अभिभावकों के नियंत्रण को मजबूत करने, स्क्रीन टाइम की एक निश्चित सीमा तय करने और कुछ संवेदनशील फीचर्स पर रोक लगाने जैसे सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र की जांच के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण बच्चे गलत जानकारी देकर आसानी से अकाउंट बना लेते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार अब अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से उन्नत पहचान प्रणालियों पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि न्यूनतम उम्र सीमा 13 वर्ष रखी जाए या इसे बढ़ाकर 16 वर्ष किया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच देखी जा रही है, जहां अक्सर एक ही मोबाइल फोन पूरे परिवार द्वारा साझा किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता की सटीक उम्र की पहचान करना और नियमों को कड़ाई से लागू करना काफी जटिल होगा। साथ ही, यदि उम्र सीमा 16 या 18 वर्ष तय की जाती है, तो डिजिटल पहुंच सीमित होने और गोपनीयता (प्राइवेसी) से जुड़े नए कानूनी सवाल भी खड़े हो सकते हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध हानिकारक सामग्री और साइबर खतरों से सुरक्षित रखना है।

ये कैसे स्मार्ट मीटर? कहीं बैलेंस होने पर भी कटी बिजली तो कहीं बिल ने उड़ाए होश; गाजियाबाद से चौंकाने वाली रिपोर्ट

गाजियाबाद, एजेंसी। विद्युत निगम ने शहरी उपभोक्ताओं के घरों से सामान्य मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, लेकिन उन्हें संचालित करने में अधिकारी फेल साबित हो रहे हैं। भुगतान करने के बाद भी सर्वर नहीं चलने से किसी का बिल अपडेट नहीं हुआ तो किसी के मीटर में बैलेंस होने के बाद भी बिजली कटी हुई है। विद्युत निगम की एप में बिल अपडेट नहीं होने से कई उपभोक्ताओं ने दो-दो बार मीटर को रिचॉर्ज कर लिया। इसके बाद भी बिजली बहाल नहीं हुई। शहर में अभी भी स्मार्ट मीटर वाले हजारों उपभोक्ता ऐसे हैं, जो बिजली बिल तो जमा कर चुके हैं पर अभी तक बिजली कटी है। किसी को बिल जमा करे हुए 48 घंटे तो किसी को 72 घंटे हो गए हैं। विद्युत निगम के कार्यालयों में इसकी शिकायत लगातार आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शिकायत करने पर

हर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उपभोक्ताओं की परेशानी को लेकर पेश है साहिबाबाद से राहुल कुमार की रिपोर्ट...

1718 रुपये होने के बाद भी दो दिन से कटी बिजली : उपभोक्ता स्नेहा बिष्ट ने बताया कि मेरे स्मार्ट मीटर में 1718 रुपये हैं। इसके बाद भी दो दिन से घर की बिजली कटी हुई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अभी तक आपूर्ति सामान्य नहीं हुई है। अब हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई है। वहां से भी केवल आश्वासन दिया गया है। उन्होंने एक्स पर शिकायत करते हुए लिखा कि 30 घंटे से सर्वर नहीं चल रहा है। जब सिस्टम चला नहीं पाते तो बनाते क्यों हो।

भुगतान करने के बाद भी बिल नहीं हुआ अपडेट : उपभोक्ता तुषार शर्मा ने बताया कि उन्होंने पहली बार 3282 रुपये और दूसरी बार में 2000 रुपये का रिचार्ज किया है। इसके बाद भी मीटर में पेमेंट अपडेट नहीं हुई है। जबकि विद्युत निगम को रिचार्ज की डिटेल भी साझा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये मीटर केवल तमाशे के लिए लगाए हैं।

मीटर लगने के कुछ दिन बाद ही 15723 रुपये आ गया बिल :

उपभोक्ता अमित सिंह ने एक्स पर यूपीपीसीएल और पीपीवीएनएल को टैग कर शिकायत करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही स्मार्ट मीटर लगा था। उसके बाद गलत बिल जारी कर दिया था। 26 मार्च को बिल सही कराया। इसके बाद फिर से 15723 रुपये का बिल जारी कर दिया है, जो गलत है।

ये आ रहीं प्रमुख समस्या

- बिल जमा करने के बाद भी बिजली जुड़ने में 24 से 72 घंटे तक लग रहे।
- स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही।
- बिल जमा करने के बाद भी बकाया बताकर काटी जा रही बिजली।
- बिजली काटने की पहले से कोई सूचना नहीं दी जा रही।
- भुगतान के बाद भी पोर्टल पर दिखा रहा अतिरिक्त बकाया बिल।
- टोल फ्री नंबर 1912 पर भी समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान।
- 7. स्थानीय अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे।